



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918171181080



+919068806410

www.vajiraoinstitute.com



info@vajiraoinstitute.com

TODAY ANALYSIS

(आज का विश्लेषण)

(13 September 2023)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- चुनाव के दौरान सभी VVPAT पर्चियों की गिनती के लिए याचिका
- भारत-रूस चेन्नई-व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारा
- भारत के पास 'चंद्रयान-3' और 'आदित्य-L1' जैसे अंतरिक्ष अभियानों के लिए कौन-से कानूनी ढांचा उपलब्ध हैं?
- केरल में निपाह का फिर से प्रकोप, 2 लोगों की मौत
- लद्दाख में LAC से कुछ दूरी पर हवाई क्षेत्र की आधारशिला रखी गई

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918171181080
+919068806410



www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com



चुनाव के दौरान सभी VVPAT पर्चियों की गिनती के लिए याचिका:

मुद्दा क्या है?

- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की एक याचिका में वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पर्चियों की 100 प्रतिशत गिनती की मांग की गई है।
- हालांकि, चुनाव आयोग का कहना है कि अगर हम हर चुनाव के लिए ऐसा करते हैं, तो यह मैनुअल पेपर वोटिंग के पुराने दिनों में वापस जाने जैसा होगा। उनका तर्क है कि यह गोलमोल तरीके से कागजी मतपत्रों को वापस लाने जैसा होगा। इसमें कहा गया है कि यह अप्रत्यक्ष तरीकों से कागजी मतपत्रों को फिर से शुरू करने के समान होगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहा है।



ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- अब तक, निर्वाचन आयोग प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच यादृच्छिक रूप से चयनित मतदान केंद्रों में सभी VVPAT पर्चियों की गिनती अनिवार्य रूप से करता है।

VVPAT क्या होता है?

- वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) भारत में चुनावों में उपयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से जुड़ी एक मशीन है। जब कोई व्यक्ति वोट देता है, तो VVPAT उनकी पसंद दिखाने वाली एक पेपर स्लिप प्रिंट करता है, जिसे मतदाता एक बॉक्स में गिरने से पहले सात सेकंड तक देख सकता है।

चुनाव प्रक्रिया में VVPAT को कब से अपनाया गया?

- VVPAT का विचार 2010 में चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच मतदान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के बारे में चर्चा के दौरान आया था।
- 2013 में, EVM में एक ड्रॉप बॉक्स के साथ एक प्रिंटर संलग्न करने की अनुमति देने के लिए चुनाव संचालन नियम, 1961 में बदलाव किया गया था।
- VVPAT का इस्तेमाल पहली बार 2013 में नागालैंड के नोकसेन विधानसभा क्षेत्र के सभी 21 मतदान केंद्रों पर किया गया था और धीरे-धीरे इसे चुनावों में पेश किया गया।

ADDRESS:



- जून 2017 से, चुनावों में 100% VVPAT का उपयोग किया जाने लगा और 2019 का लोकसभा चुनाव पहला आम चुनाव बन गया जिसमें 100% EVM को VVPAT से जोड़ा गया, जो चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

मौजूदा याचिका क्या मांग कर रही है?

- इसी साल मार्च में चुनाव निगरानी समूह ADR ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करते हुए, सभी VVPAT पर्चियों की गिनती करने के लिए, तर्क दिया कि यद्यपि मतदाता अपना वोट पर्ची पर सात सेकंड के लिए देख सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं है कि यह मत वास्तव में उनकी इच्छानुसार गिना गया है।
- ऐसे में ADR चाहता है कि सर्वोच्च न्यायालय यह घोषित करे कि प्रत्येक मतदाता को यह सुनिश्चित करने का मौलिक अधिकार है कि उसका वोट सही ढंग से दर्ज और गिना जाए, जिसका अर्थ है सभी VVPAT पर्चियों की गिनती होनी चाहिए।

निर्वाचन आयोग का इस मामले में क्या कहना है?

- अपने जवाबी हलफनामे में, चुनाव आयोग ने कहा कि भारत में 4,000 से अधिक कुल विधानसभा सीटों के साथ प्रति विधानसभा सीट पर पांच यादृच्छिक रूप से

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



चयनित मतदान केंद्रों के VVPAT का सत्यापन किया गया, जो कुल 20,600 EVM-VVPAT प्रणालियों हुई - जो कि ISI की 479 की सिफारिश से काफी ऊपर है।

- चुनाव आयोग (EC) ने उल्लेख किया है कि पिछले चुनावों में, उन्होंने 38,156 VVPAT की जांच की है और एक उम्मीदवार के वोट दूसरे को जाने का कोई मामला नहीं मिला है। हालांकि, गिनती में कुछ अंतर मानवीय त्रुटियों के कारण थे, जैसे परीक्षण वोटों को अलग न करना।
- 2017 में VVPAT की शुरुआत के बाद से, चुनाव आयोग को वोट डालने वाले 118 करोड़ मतदाताओं में से केवल 25 शिकायतें मिली हैं, और ये सभी शिकायत झूठी पाई गईं।
- चुनाव आयोग ने बताया कि VVPAT मतदाताओं के लिए तत्काल जांच करने एवं उनकी संतुष्टि के लिए लाया गया है, लेकिन सांख्यिकीय रूप से विश्वसनीय तरीके से अतिरिक्त जांच करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी पालन किया जा रहा है।
- सरल शब्दों में, आयोग कह रहा है कि चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए VVPAT अच्छा काम कर रहे हैं।
- यह मामला अब 3 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



भारत-रूस 'चेन्नई-व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारा (EMC)':

चर्चा में क्यों है?

- भारत और रूस "चेन्नई-व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारे (EMC)" को शीघ्रता से क्रियान्वित करने के लिए उत्सुक हैं, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्ग है।
- रूस की अपनी यात्रा के दौरान, केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 12 सितंबर को व्लादिवोस्तोक में 'पूर्वी समुद्री गलियारे (EMC)' पर एक भारत-रूसी कार्यशाला के लिए निमंत्रण दिया।



- रूस सरकार भी इसमें रुचि रखती है अपने भारतीय समकक्षों के साथ द्विपक्षीय चर्चा में शामिल होने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल को चेन्नई भेजना चाहती है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



पूर्वी समुद्री गलियारा (EMC) का रणनीतिक रूप से महत्व:

- पूर्वी समुद्री गलियारा (EMC) रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत को व्यापार मार्ग के माध्यम से दक्षिण चीन सागर तक पहुंच प्रदान करता है।
- यह समुद्री मार्ग विशेष रूप से एक मूल्यवान संसाधन 'कोकिंग कोल' के तेज परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- EMC को चालू करना भारत और रूस के बीच व्यापार संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर और रास्ते खुलेंगे।

पूर्वी समुद्री गलियारा (EMC) के बारे में:

- सितंबर 2019 में व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की उपस्थिति में व्लादिवोस्तोक और चेन्नई के दो बंदरगाहों के बीच समुद्री मार्ग के विकास पर आशय ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया।
- इसके बाद, एक स्वतंत्र अध्ययन में पाया गया कि EMC के द्वारा कोकिंग कोयला सबसे उपयुक्त वस्तु है। आने वाले समय में, इस मार्ग के माध्यम से परिवहन की जाने वाली वस्तुओं की सूची में पेट्रोलियम, एलएनजी, उर्वरक जैसी अधिक वस्तुओं को जोड़ा जाएगा।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- अनुमान है कि पूर्वी समुद्री गलियारा (EMC) भारत और रूसी सुदूर-पूर्व क्षेत्र के बंदरगाहों के बीच माल परिवहन के लिए आवश्यक समय को वर्तमान में 40 दिनों की तुलना में 16 दिनों तक, यानी 24 दिनों तक कम कर देगा।
- इस गलियारे में व्यापार और सहयोग के नए अवसरों को खोलने की अपार संभावनाएं हैं।

ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम या पूर्वी आर्थिक मंच क्या है?

- ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है जहां रूस और वैश्विक निवेशक समुदाय एक साथ आते हैं। वे रूसी सुदूर पूर्व की आर्थिक क्षमता पर चर्चा और आकलन करते हैं, वहां निवेश के अवसरों को देखते हैं और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में व्यावसायिक स्थितियों पर विचार करते हैं।
- इसे 2015 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा रूस के सुदूर पूर्व में अर्थव्यवस्था को विकसित करने और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ सहयोग बढ़ाने में मदद करने के लिए बनाया गया था।

भारत में समुद्र तटीय एवं बंदरगाह की अवसंरचना विकास की स्थिति:

- **सागरमाला कार्यक्रम:**
 - 2015 में, भारत के समुद्र तट और जलमार्गों की पूरी क्षमता को अनलॉक करके, भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सागरमाला की परिवर्तनकारी प्रमुख पहल शुरू की गई थी।

ADDRESS:



- सागरमाला का दृष्टिकोण बंदरगाह के नेतृत्व वाले विकास के माध्यम से अनुकूलित बुनियादी ढांचे के निवेश के साथ घरेलू और एक्जिम कार्गो दोनों के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम करना है।
- वर्तमान में, सागरमाला परियोजना के तहत 2035 तक कार्यान्वयन के लिए 65 अरब डॉलर से अधिक के निवेश की 802 परियोजनाएं हैं।
- **तटीय जिलों के समग्र विकास योजना** तहत, लगभग 7 अरब डॉलर की अनुमानित लागत वाली कुल 567 परियोजनाओं की पहचान की गई है।
- **प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान:**
 - इस कार्यक्रम के माध्यम से रेलवे, सड़क मार्ग, जलमार्ग और वायुमार्ग के विकास के द्वारा एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से उत्पादकता और रोजगार के अवसरों में सुधार के लिए समग्र बुनियादी ढांचे के विकास की कल्पना की गयी है।
 - यह योजना नए जमाने की तकनीक और अत्याधुनिक नवाचार का उपयोग करके विश्व स्तरीय उत्पादों के निर्माण के लिए भारत के कायाकल्प का आधार बन गई है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918171181080
+919068806410



www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com



भारत के पास 'चंद्रयान-3' और 'आदित्य-L1' जैसे अंतरिक्ष अभियानों के लिए कौन-से कानूनी ढांचा उपलब्ध हैं?

संदर्भ:

- संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के बाद भारत अब उन चार देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है, जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारा है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव के इतने करीब ऐसा करने वाला यह पहला है, जहां पानी की मौजूदगी के सबूत मिले हैं।
- जैसा कि भारत अपने चंद्र मिशन की सफलता और एक नए सौर अन्वेषण मिशन के लॉन्च का जश्न मना रहा है, हम उन कानूनों पर नजर डालते हैं जो अंतरिक्ष उद्यमों को नियंत्रित करते हैं, और क्या किया जाना बाकी है।



ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



अंतरिक्ष से सम्बन्धी कानूनी ढांचे की आवश्यकता क्यों बढ़ रही है?

- भारत, अपने तुलनात्मक रूप से कम बजट वाले अंतरिक्ष कार्यक्रम के बावजूद, सक्रिय रूप से महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष उद्योग को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें इसके आगामी कू मिशन (गगनयान) और आर्टेमिस समझौते, जो अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए गैर-बाध्यकारी सिद्धांतों का एक सेट है, में भागीदारी है।
- राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों और निजी कंपनियों के साथ, भारत चंद्रमा तक पहुंचने की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष दौड़ का हिस्सा है। ये मिशन वैश्विक मंच पर स्थान सुरक्षित करते हुए वाणिज्यिक और रणनीतिक दोनों हितों की पूर्ति करते हैं।
- इस संदर्भ में, ऐसे अंतरिक्ष उद्योग को नियंत्रित करने वाले अंतरराष्ट्रीय कानूनों और घरेलू नियमों के बारे में सवाल उठते हैं, जो इस तेजी से विकसित हो रहे अंतरिक्ष अन्वेषण परिदृश्य में व्यापक कानूनी ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

अंतरिक्ष उद्योग के लिए उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचा क्या है?

- संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) ने हाल ही में अपनी संक्षिप्त नीति वक्तव्य में "सभी मानवता के लिए - बाहरी अंतरिक्ष प्रशासन का भविष्य" में बाहरी अंतरिक्ष में शांति, सुरक्षा और हथियारों की दौड़ की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए एक नई संधि के विकास की सिफारिश की।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून का मार्गदर्शन करने वाले मूल सिद्धांतों में से एक "रेस कम्युनिस है - कुछ प्राकृतिक संसाधनों पर मानव जाति द्वारा साझा स्वामित्व" की अवधारणा।
- **बाह्य अंतरिक्ष संधि - 1967:**
 - 1967 में स्थापित "बाह्य अंतरिक्ष संधि", अंतरिक्ष कानून में एक मूलभूत दस्तावेज है, जिसे अक्सर अंतरिक्ष का मैग्नाकार्टा कहा जाता है।
 - यह हस्ताक्षरकर्ता राज्यों को विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष का उपयोग करने के लिए बाध्य करता है, अंतरिक्ष के सैन्यीकरण पर रोक लगाता है, और आकाशीय पिंडों पर संप्रभुता के दावों को अस्वीकार करता है।
- **"बचाव समझौता-1968 ":**
 - "बचाव समझौता" अंतरिक्ष यात्रियों के बचाव, अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी और बाहरी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित वस्तुओं की वापसी पर समझौते को संदर्भित करता है।
 - 1968 में अपनाई गई यह अंतरराष्ट्रीय संधि, अंतरिक्ष कानून को नियंत्रित करने वाली पांच प्रमुख संयुक्त राष्ट्र संधियों में से एक है।



- **“अंतर्राष्ट्रीय दायित्व पर कन्वेंशन, 1972”:**

- आधिकारिक तौर पर अंतरिक्ष वस्तुओं के कारण होने वाले नुकसान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व पर कन्वेंशन, यह समझौता 1 सितंबर, 1972 को लागू हुआ।
- इस संधि के तहत, अंतरिक्ष में किसी वस्तु को लॉन्च करने वाला देश पृथ्वी की सतह या विमान या उसकी अपनी गलती के कारण बाहरी अंतरिक्ष में होने वाली किसी भी क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।

- **"चंद्रमा समझौता, 1984":**

- चंद्रमा समझौता, जिसे औपचारिक रूप से चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों पर राज्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले समझौते के रूप में जाना जाता है, 11 जुलाई, 1984 को लागू हुआ।
- यह चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के शांतिपूर्ण उपयोग और उनके पर्यावरण की सुरक्षा को सुदृढ़ करता है।
- विशेष रूप से, यह चंद्रमा के प्राकृतिक संसाधनों को मानवता की साझी विरासत के रूप में नामित करता है और इन संसाधनों के दोहन को नियंत्रित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना का आह्वान करता है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



चंद्रमा पर खनन - एक कानूनी ग्रे जोन:

- अंतरिक्ष में निजी वाणिज्यिक खिलाड़ियों का उदय, नासा द्वारा चंद्रमा के रेजोलिथ निष्कर्षण के लिए कंपनियों को अनुबंधित करना, वाणिज्यिक अंतरिक्ष खनन के युग की शुरुआत करता है।
- चंद्रमा और क्षुद्रग्रह जैसे आकाशीय पिंड प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यवान स्रोत हैं। हाल ही में प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा पर पानी और विभिन्न खनिज तत्व मिले हैं, जो खगोलीय पिंड की खनिज क्षमता को उजागर करते हैं।
- जबकि अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ राष्ट्रों को आकाशीय पिंडों के स्वामित्व का दावा करने से रोकती हैं, वे निष्कर्षण के बाद संसाधन स्वामित्व को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं करती हैं।
- अमेरिका, लक्ज़मबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात और जापान जैसे कुछ देशों ने घरेलू कानून पारित किए हैं जो कंपनियों को निकाले गए अंतरिक्ष संसाधनों पर विशेष अधिकारों का दावा करने की अनुमति देते हैं। अमेरिका ने, विशेष रूप से, *अंतरिक्ष संसाधनों पर निजी संस्थाओं के संपत्ति अधिकारों को मान्यता देते हुए, 2015 में यूएस वाणिज्यिक अंतरिक्ष लॉन्च प्रतिस्पर्धात्मकता अधिनियम लागू किया।*

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



भारत की अंतरिक्ष नीति 2023 - अंतरिक्ष खनन के लिए तैयारी:

- भारतीय अंतरिक्ष उद्योग को निजी कंपनियों के लिए खोलने का प्रयास काफी समय से चल रहा है। वास्तव में, इसरो और भारतीय निजी क्षेत्र के बीच एक संयुक्त परियोजना के रूप में चंद्रयान-3 इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर दर्शाता है।
- 2017 में एक अंतरिक्ष गतिविधि विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था लेकिन 2019 में पास न हो पाने के कारण यह समाप्त हो गया।
- इसरो ने 20 अप्रैल 2023 को *'अंतरिक्ष में एक समृद्ध व्यावसायिक उपस्थिति को सक्षम करने, प्रोत्साहित करने और विकसित करने'* की दृष्टि से भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जारी की।
- भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023:
 - इसरो द्वारा जारी इस नीति का उद्देश्य अंतरिक्ष में एक संपन्न व्यावसायिक उपस्थिति को बढ़ावा देना, अंतरिक्ष संसाधन निष्कर्षण, सौर ऊर्जा, क्षुद्रग्रह खनन और चंद्र खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- इसरो अब अपना ध्यान अंतरिक्ष अनुसंधान और राष्ट्रीय हित से संबंधित अन्वेषण पर केंद्रित करेगा, जबकि विनिर्माण और संचालन का प्रबंधन न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) द्वारा किया जाएगा।
- 'भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACE)' नई अंतरिक्ष संस्थाओं (NGE) के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए एक नियामक ढांचा तैयार करेगा।

क्या भारत को घरेलू अंतरिक्ष कानून की आवश्यकता है?

- भारत जैसे विकासशील देशों के लिए, अंतरिक्ष कानून की आवश्यकता और भी अधिक स्पष्ट है, क्योंकि यह क्षमता निर्माण प्रयासों की नींव के रूप में काम कर सकता है, निवेश आकर्षित कर सकता है, घरेलू अंतरिक्ष उद्योग के विकास को बढ़ावा दे सकता है और आपदा प्रबंधन, कृषि और शहरी नियोजन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक लाभ के लिए अंतरिक्ष संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकता है।
- अंतरिक्ष कानून ढांचे का एक अन्य प्रमुख कारण अंतरिक्ष स्थिरता और अंतरिक्ष मलबे से होने वाले नुकसान की रोकथाम और "केसलर सिंड्रोम" से सुरक्षा प्रदान करना है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918171181080
+919068806410

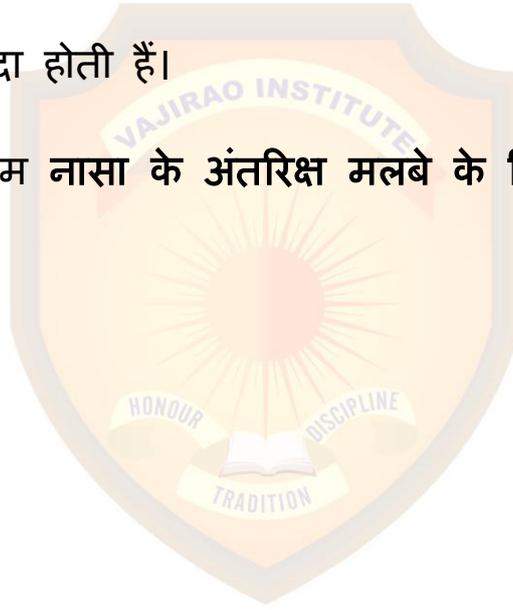


www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com



"केसलर सिंड्रोम" क्या है?

- केसलर सिंड्रोम एक ऐसी घटना है जिसमें पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा में मलबे की मात्रा एक बिंदु तक पहुंच जाती है जहां यह अधिक से अधिक अंतरिक्ष मलबे का निर्माण होता है, जिससे उपग्रहों, अंतरिक्ष यात्रियों और मिशन योजनाकारों के लिए बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं।
- केसलर सिंड्रोम का नाम नासा के अंतरिक्ष मलबे के विशेषज्ञ डॉन केसलर के नाम पर रखा गया है।



ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918171181080
+919068806410



www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com



केरल में 'निपाह' का फिर से प्रकोप, 2 लोगों की मौत:

चर्चा में क्यों है?

- मंगलवार 12 सितंबर को कोझिकोड जिले से दो मौतों की खबर के साथ, निपाह का डर केरल में लौट आया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने पुष्टि की कि मौतें निपाह वायरस के कारण हुईं।



- उन्होंने कहा कि चार संदिग्ध मामले फिलहाल निगरानी में हैं और उनके नमूने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे भेजे गए हैं।
- इससे पहले, 2018 और 2021 में कोझिकोड जिले में निपाह वायरस संक्रमण के कारण मौतें दर्ज की गई थीं।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



'निपाह' वायरस:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, निपाह वायरस का मृत्यु अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है, और यह दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत डब्ल्यूएचओ क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व की एक उभरती हुई जूनोटिक बीमारी है।
- मनुष्यों में निपाह वायरस संक्रमण कई प्रकार की नैदानिक प्रस्तुतियों का कारण बनता है, जिसमें गैर-लक्षण संक्रमण से लेकर तीव्र श्वसन संक्रमण और घातक एन्सेफलाइटिस शामिल हैं।

निपाह वायरस का संक्रमण दर एवं भयावहता:

- निपाह वायरस SARS-CoV-2 की तुलना में कहीं अधिक धीरे-धीरे फैलने के लिए जाना जाता है।
- हालांकि, इसमें मृत्युदर का अधिक होना ही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। 2001 में बंगाल के सिलीगुड़ी में पहले प्रकोप के दौरान, संक्रमित होने की पुष्टि करने वाले 66 लोगों में से 45 की मृत्यु हो गई, यानी मृत्यु दर 68% है। 2018 में केरल में प्रकोप के दौरान, संक्रमित होने की पुष्टि किए गए 18 रोगियों में से 17 की मृत्यु हो गई।
- इसमें मृत्यु दर 40% से 75% अनुमानित है।

ADDRESS:

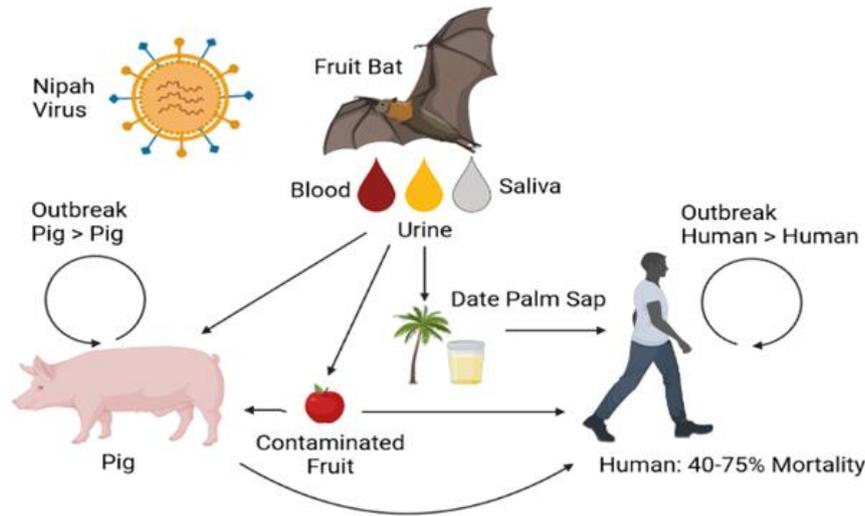


- लोगों या जानवरों के लिए कोई इलाज या टीका उपलब्ध नहीं है। मनुष्यों के लिए प्राथमिक उपचार सहायक देखभाल है।

निपाह कैसे फैलता है?

- निपाह वायरस जानवरों (जैसे चमगादड़ या सूअर) या दूषित खाद्य पदार्थों से मनुष्यों में फैल सकता है और सीधे इंसान से इंसान में भी फैल सकता है।
- टेरोपोडिडे परिवार के फल चमगादड़ निपाह वायरस के प्राकृतिक मेजबान हैं।
- मनुष्यों के बीच निपाह वायरस का पहला प्रकोप मलेशिया (1998) और सिंगापुर (1999) में रिपोर्ट किया गया था।

Nipah Virus Transmission and Mortality



- इस वायरस का नाम मलेशिया के उस गांव से लिया गया है जहां जिस व्यक्ति में यह वायरस सबसे पहले आया था उसकी इस बीमारी से मृत्यु हो गई थी।

ADDRESS:



लद्दाख में LAC से कुछ दूरी पर हवाई क्षेत्र की आधारशिला रखी गई:

चर्चा में क्या है?

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सितंबर को चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के बहुत करीब पूर्वी लद्दाख में न्योमा हवाई क्षेत्र की आधारशिला रखी और अरुणाचल प्रदेश में तवांग में महत्वपूर्ण नेचिफू सुरंग का भी उद्घाटन किया।



- कुल मिलाकर उन्होंने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा ₹2,900 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें पश्चिम बंगाल में दो संशोधित हवाई क्षेत्र, बागडोगरा और बैरकपुर, दो हेलीपैड, 22 सड़कें और 63 पुल शामिल हैं।

ADDRESS:



न्योमा हवाई पट्टी:

- लगभग ₹200 करोड़ की लागत से विकसित होने वाला न्योमा हवाई पट्टी, लद्दाख में हवाई बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगा और उत्तरी सीमा पर भारतीय वायुसेना की क्षमता को बढ़ाएगा।
- रक्षा मंत्री ने विश्वास जताया कि यह हवाई क्षेत्र, जो दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक होगा, सशस्त्र बलों के लिए गेम-चेंजर साबित होगा।
- एक बार पूरा होने पर इसका रनवे भारतीय वायुसेना के सभी लड़ाकू जेटों को संचालित करने में सक्षम होगा।
- 'न्योमा' गांव लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट के करीब स्थित है।
- न्योमा चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से करीब 46 किलोमीटर दूर है।

नेचिफू सुरंग:

- 500 मीटर लंबी नेचिफू सुरंग, जिसका काम अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ, अरुणाचल प्रदेश में "बालीपारा-चारिद्वार-तवांग रोड" पर एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है।
- निर्माणाधीन सेला सुरंग के साथ यह सुरंग रणनीतिक तवांग क्षेत्र को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।

ADDRESS: